म्यांमार : लोकतन्त्रकी बहालीपर प्रश्नचिह्न

आज (चतुर्थी), 13.04.2012

'म्यांमारमें मतदानके एक हफ्तासे ज्यादा गुजर जानेके बावजूद चुनाव आयोगने चुप्पी साध रखी है, जबकि सरकारी घोषणाके मुताबिक एक हफ्तेमें परिणाम घोषित होने थे। दुनियाकी सबसे लम्बी लड़ाई लड़ रहे केएनयू प्रतिनिधिमण्डलसे सूकीकी मुलाकातका सरकारी पक्ष दूसरा रंग दे रहा है।

□ शशिधर खान

आखिरकार एक अप्रैल, २०१२ को बहुप्रतीक्षित संसदीय उपचुनाव तो हुए, लेकिन इसमें भी मतदान शुरू होनेसे लेकर समाप्त होनेतक आशंकाओंको आशंका बनी रही। इसके लिए पहली बार यूरोपीय देशोंके पर्यवेक्षकोंको बंगलूर आने और मतदान सम्पन्न होनेतक रहनेकी इजाजत दी गयी थी, क्योंकि उन्हें दिखानेके लिए 'निष्पक्ष' मतदान कराना था, ताकि यूरोपीय देश आर्थिक प्रतिबन्ध हटानेमें और उदारता दिखायें। भारतने भी म्यांमारकी सीमावर्ती राज्य असम और मणिपुरके चुनाव अधिकारियोंको 'निगरानी' के लिए भेजा था।

म्यांमार स्थित भारतीय राजदूत पहलेसे ही तैनात थे। उसके बावजूद मतदानमें गड़बड़ीकी सम्भावना बरकरार रही। सू कीने भी पहले ही मतदानकी निष्पक्षताको संदिग्ध बताते हुए कह दिया था कि इस उपचुनावका परिणाम भी पहलेसे आम चुनाव जैसा आनेकी सम्भावनासे इनकार नहीं किया जा सकता और वैसा उन्होंने कहा, अमूमन वैसा ही हुआ। इस बार ४५ सीटोंके लिए 'खुले दिमाग' से कराये गये मतदानके दिन सू की समर्थक एनएलडी कार्यकर्ताओंने अपने नेताकी भारी जीतका एकतरफा जश्न मना लिया, जबकि आधिकारिक तौरपर न तो चुनाव परिणाम घोषित हुआ, न ही सूकीकी जीतकी पुष्टि। सरकार, चुनाव आयोग सबकी रहस्यमय चुप्पीके बीच आधिकारिक परिणाम घोषित हुए बिना ही सू की समर्थक खुशीमें नाचते-झूमते रहे। बड़ी संख्यामें कार्यकर्ता मतदाता सूचीमें अपना नाम न होनेकी वजहसे वोट ही नहीं डाल पाये। कइयोंने मतपत्रकी छपाईमें बड़ी सम्भावनासे की गयी हेराफेरीकी भी शिकायत की। एनएलडीके बैनर तले १७ राजनीतिक दलोंके उम्मीदवारोंके नाम मिटाने और उनके पक्षमें पड़े वोट रद करनेके इरादेसे मतपेटीके मतपत्र गिननेवाले संकरे छेदमें इस हिसाबसे मोम चिपकाया गया था ताकि एनएलडी बैनर तले खड़े १७ पार्टियोंके उम्मीदवारोंके नाम मिट जायें और उनके पक्षमें पड़े वोट रद किये जा सकें।



सू कीने भी पहले ही मतदानकी निष्पक्षताको संदिग्ध बताते हुए कह दिया था कि इस उपचुनावका परिणाम भी पहलेकी तरह आम चुनाव जैसा आनेकी सम्भावनासे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार 'खुले दिमाग' से कराये गये मतदानके दिन सू की समर्थक एनएलडी कार्यकर्ताओंने अपने नेताकी भारी जीतका एकतरफा जश्न मना लिया, जबकि आधिकारिक तौरपर न तो चुनाव परिणाम घोषित हुआ, न ही सूकीकी जीतकी पुष्टि।

एनएलडी प्रवक्ताने बताया कि उन्होंने संघीय चुनाव आयोगको शिकायत पत्र तो भेजा, लेकिन जानते थे कि इससे कुछ होना-जाना नहीं है। वे वो ४५ सीटें हैं, जो नवम्बर, २०१० चुनावमें रिक्त रह गयी थीं, क्योंकि सैनिक वर्दी त्यागकर लुंगी पहनकर सिविलियन बने जनरल संचालित सत्तारूढ़ यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेवलपेष्ट पार्टीको उतने 'सिविलियन' उम्मीदवार नहीं मिले। संसदकी ६६४ सीटोंमें दो-तिहाई सैनिकोंके लिए आरक्षित होनेके कारण पूर्ण बहुमतमें तो सत्तारूढ़ सैनिक जुंटाको रहना ही था। उस समय सू कीको चुनाव परिणाम घोषित होनेके बाद जेलसे रिहा किया गया। इस बार यह कहकर उपचुनाव कराये गये कि सू की चुनाव लड़ेंगी। सैनिक सरकारको सू कीकी जीतकर आने और निचले सदनका सदस्य बनकर सरकारमें भी भागीदारीमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बातका एकतरफा प्रचार सिर्फ दुनियाके अन्य देशोंको झांसेमें रखनेके लिए किया गया है। यदि वह सरकारमें शामिल भी होती हैं तो उनकी भूमिका सरकारकी किसी नीतिका विरोध करनेवाली नहीं हो सकती। सबसे रोचक तो यह रहा कि चीनकी सरकार समाचार एजेंसी 'शिन्हुवा' ने भी सर्वप्रथम सू की समर्थकोंके जीतका जश्न मनाते देखा और उनके सरकारमें शामिल होनेकी सम्भावना प्रचारित की।

सू कीने अपने गृह चुनाव क्षेत्र काउमसे पर्चा भरा, जहांसे १९९० में भारी मतोंसे जीतनेके बावजूद सू की और उनके सहयोगी दलोंके पूर्ण बहुमतको इसी सरकारने मान्यता नहीं दी। फिर नवम्बर, २०१० के आम चुनावमें सू की और उनके समर्थकोंको जेलमें बन्द रखकर मतदान कराये गये। इसलिए सू कीने चुनावका बायकाट किया। एक अप्रैल, २०१२ का उपचुनाव भी कायदेसे देखा जाय तो उसी छलावा जन-तान्त्रिक सुधार 'प्रक्रिया' की एक चालाकीभरी करतूत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण मकसद यूरोपीय देशोंकी सहानुभूति हासिल करना है, ताकि वे जनतन्त्रकी दिशामें कुछ कदम उठाते देखकर 'आश्वस्त' हो जायं और कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध हटानेकी दिशामें सोचें। दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है, विपक्षी आन्दोलनका एक प्रकारसे लोप, जो सू कीके संसद सदस्य बनते ही हो जानेकी सम्भावना है। अब वे पहलेकी तरह सैनिक सरकारकी नीतियोंका सड़कपर उतरकर खुलेआम विरोध नहीं कर पायगी और न ही संसदमें सूकी और उनके समर्थक दलोंके सदस्य कोई प्रभावी भूमिका निभा पायेंगे। वास्तवमें वे सिर्फ कहनेके लिए विपक्षी होंगे, उनके पास सरकारी नीतियोंके समर्थनके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर विरोध भी करें तो बेअसर साबित होगा, क्योंकि पूरी संसदपर यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेवलपमेण्ट पार्टीका कब्जा है, जो जीते नहीं, जितवाये गये हैं। यह उपचुनाव इसलिए कराया गया है, ताकि कमजोर विपक्ष भी न हो। सैनिक सरकारने पहलेसे ही कह रखा है कि सूकीकी सरकारमें भागीदारी हो सकती है। इसलिए उपचुनावसे पहले ऐसा संविधान बनाया गया ताकि संसदपर पूर्व सैनिक अधिकारियोंका ही वर्चस्व हो। एक अप्रैलके मतदानको फिलीपींस डेली ने 'अप्रैल फूल' की संज्ञा देते हुए अपनी टिप्पणीमें कहा था कि बड़ी समझदारीसे मतदाताओंको मूर्ख बनानेका इन्तजाम लगानेके बाद उपचुनावका झांसा यह बतानेके लिए दिया गया कि १९६२ के सैनिक तख्तापलट नेता नूनको हटाकर तानाशाही व्यवस्था कायम करनेवाले जनरल ने विन युगकी समाप्ति और नये युग 'जनतन्त्र बहाली' की शुरुआत है। वैसी संवैधानिक व्यवस्थामें ऐसे चुनावका कोई अर्थ नहीं रह जाता, जिसमें सैनिक जुंटाका देशपर पूर्ण नियन्त्रणका प्रावधान है। सैनिक जुंटाके पास यह अधिकार 'सुरक्षित' है कि जब चाहे यह सारे तथाकथित 'उदारवादी' कदम वापस लेकर मार्शल लॉ लागू कर दे।

आम मतदाताओंके लिए कई बातें समझना कठिन हैं, जिसमें एक यह भी है कि सरकारमें महत्वपूर्ण पद हासिल करनेवालेको संसदकी सीट छोड़नी होगी। सैनिक सरकारकी सफाईके मुताबिक इसी प्रावधानके चलते सीटें रिक्त हुई और उपचुनावके जरिये सूकीको चुनाव लड़नेका अवसर मिला। ४५ सीटें उन सैनिक अधिकारियोंने छोड़ी, जिन्हें सरकारमें अन्य महत्वपूर्ण पद दिये गये। ऐसा 'महत्वपूर्ण' आफर सूकीको भी चुनावकी घोषणासे पहलेसे दिया जा रहा है, ताकि वे सुधारोंमें ज्यादा 'योगदान' कर सकें। लेकिन इसके लिए सूकीको संसदकी सीट छोड़नी होगी। अन्य लोकतान्त्रिक देशोंकी तरह वहां चुनाव आयोग कोई स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका संचालन उन्हीं सैनिक जनरलों द्वारा नियुक्त सैनिक अधिकारी करते हैं, जो सरकार चला रहे हैं और ऐसा ही अनुभव चाहते हैं, जिसमें जनादेश उनके खिलाफ जानेके बावजूद गद्दी न छोड़नी पड़े। इसीलिए यह नाटक अपने आपमें बड़ा दिलचस्प रहा कि सत्तारूढ़ पार्टीने ही विपक्षपर हिंसा और मतदाताओंको डराने-धमकाने 'पश्चिमके इशारेपर' की 'शिकायत' चुनाव आयोगसे की। परिणाम घोषित करनेसे ज्यादा जल्दबाजी चुनाव आयोगने सिर्फ सूकीको लक्ष्य करके लगाये गये आरोपोंकी जांचमें दिखायी।

मतदानके एक हफ्तासे ज्यादा गुजर जानेके बावजूद चुनाव आयोगने चुप्पी साध रखी है, जबकि सरकारी घोषणाके मुताबिक एक हफ्तेमें परिणाम घोषित होने थे।

म्यांमारकी आजादीके समयसे ही 'अलग आजाद कारेन प्रान्त' की मांगके लिए दुनियाकी सबसे लम्बी लड़ाई लड़ रहे केएनयू प्रतिनिधिमण्डलसे सूकीकी मुलाकातका सरकारी पक्ष दूसरा रंग दे रहा है। ४३ सीटें जीतनेका दावा अभीतक एनएलडीकी ओरसे ही किया जा रहा है और ३० अप्रैलतक उनके संसद पहुंचनेकी भी सूचना प्रचारित की गयी है। लेकिन चुनाव आयोगने ऐसा रुख अपना रखा है, मानो परिणाम घोषित होना, न होना कोई मायने नहीं रखता हो। ३-४ अप्रैलको दक्षिण पूर्व एशियाई देशोंके संघटन 'आसियान' कम्बोडियाकी राजधानी नोमपेन्ह बैठकमें म्यांमारके बदले हुए रवैयेकी तारीफ करनेवाले प्रतिनिधि भी अब पश्चिमकी तरह 'वेट एण्ड वाच' वाली नीति अपनानेको विवश हैं, जैसा कि 'फिलीपींस डेली' अखबारका कहना है।